(ग) क्या सरकार इस समस्या के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश में एन० डी० डी० बी० पैटर्न पर प्रोक्यूरमेंट तथा सेल प्रारम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है , और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) कृषि मत्रालय को राज्यो से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नही मिली है कि सब्जी और फल विक्रेताओं उत्पादको को उपभोक्ता द्वारा दी गई कीमत का सिर्फ चौथा हिस्सा ही मिलता है और शेष बिचौलियो द्वारा हड़प लिया जाता है ।

(ग) और (घ) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की पद्धति के अनुसार इस समय फल तथा सब्जियों की अधिप्राप्ति तथा बिक्री प्रारम्भ करने के लिए कृषि मत्रालय का कोई प्रस्ताव नही है।

नींबू वर्गीय फलों के लिए अनुसंधान केन्द्र

2933. **श्री अजीत जोगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के अन्तर्गत देश में कितने नीबू वर्गीय फलों के लिए अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किए गए है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव लम्बित है ; और

(ग) यदि हा, तो क्या उसे सातवी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है ?

कृषि मत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रत्यक्ष नियत्रण मे दो नीबू वर्गीय फल अनुसन्धान केन्द्र है और भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त करने वाले राज्य कृषि विश्वविद्यालयो मे सात केन्द्र है ।

(ख) जी नही, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न ही नही उठता ।

Disbursement and Utilisation of Drought Assistances

2934. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the details of the ceiling of Central assistance sanctioned to states for drought and disbursed in 1985-86, 1986-87 and current *ad-hoc* sanction and disbursement and what is the utilisation by the States; and

(b) what are the norms for severely drought affected areas and which are the areas covered under these norms currently?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA). (a) Information on ceilings of expenditure approved and central assistance released for drought relief during the years 1985-86, 1986-87 and 1987-88 is given in the Annexure. (*See* Appendix CXLIV, Annexure No 133] Central assistance to States for relief of natural calamities is released in the light of utilisation reported by the State Governments, limited to the ceilings approved for different purposes.

(b) (*See* Appendix CXLIV, Annexure No. 133] The quantum of central assistance to States/Union Territories in the wake of drought is approved after taking into account all the relevant factors including the severity of the drought in affected areas.